आधुनिकीकरण, पुनः निर्माण और श्रमिकों के स्वैच्छिक सुव्यवस्थीकरण की परिकल्पना की गई है ; ऐसी आशा है कि ग्रामीण सुधार नीति के कार्यान्वयन के पश्चात एन टी सी मिलें और बी आई सी की वस्त्र मिलें आर्थिक रूप से अर्थक्षम हो जाएंगी।

Decline in Cloth Production

790. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the total cloth production in the country in all the three sectors namely mill, powerloom and handloom during the years 1990-91. 1991-92 and 1992-93;

(b) whether the cloth production has registered a sharp decline since the last year;

(c) whether it is a fact that the Textile Industry has failed to take advantage of the concessions extended by Government if so, what are the reasons therefore; and

(d) what steps are being taken to augment textile production which is a big area for exports as well as employment in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) The total cloth production in the country in all the three sectors namely mill, powerloom and handloom during the years 1990-91, 1991-92 and 1992-93 are;

(Mill. Sq. Mtrs)

Year	Mill Sector	Power-loom Sector	Hand-loom Sector
1990-91	2589	16044	4295
1991-92	2376	16089	4123
1992-93 (Estimate)	2255	16630	4255

(b) In 1991-92 nominal fall in production has been registered.

(c) No, Sir.

(d) Government have taken various steps to augment textile production such as:

1. Restriction of creation and expansion of capacity has been removed subject only to locational guidelines.

2. Requirement of licencing has been done away with.

3. Measures are taken to ensure availability of raw material for the industry through policy intervention whenever necessary.

4. Textile Machinery can be imported and duty on such machinery has already been reduced.

उत्तर प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र का विकास

791. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान हथकरघों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश से किस-किस प्रकार के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हथकरघों के विकास के लिए वास्तव में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकट स्वामी): (क) गत दो वर्षों के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में ऊनी हथकरघा विकास परियोजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, निःसहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना, जनता कपड़ा योजना आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य को हथकरघों के विकास के लिए जारी की गई राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि लाखों में
1989-90	3191.32
1990-91	4499.84
1991-92	3769.42

उत्तर प्रदेश में तकलों का वितरण

792. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तकलों को वितरित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है

जिनके तहत उत्तर प्रदेश में कताई तथा सूत मिलों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) बुनकर सहकारी कताई मिलों की अंश पूंजी में भाग लेने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सरकार नई हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से ऋण सहायता देती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम और आधुनिक बनाया जा सके। आठवीं योजना के दौरान 2 नई कताई मिलों को सहायता देने और 4 वर्तमान कताई मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में अब तक 2 लाख से भी अधिक तकले (स्पिन्डल) लगाये गये है।

जनता कपड़े के वितरण के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन न किया जाना

793. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता कपड़े के वितरण के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार को इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा सभी कार्यान्वयन राज्यों को जारी की गई व्यापक मार्गदर्शिका के आधार पर किया जाता है। इस मार्गदर्शिका के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण को अपने उत्पादन का कम से कम 85% उपभोक्ता सहकारी समितियों और लोक वितरण प्रणाली की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले इसी प्रकार के अभिकरणों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव/हथकरघा के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की कार्यान्वयन समितियों जिनमें नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, उपभोक्ता प्रतिनिधियों, अन्य विशेषज्ञों आदि को शामिल किया गया है, को अपने-अपने राज्यों में वितरण व्यवस्था की देख-रेख के कार्य सौंपे गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) तथापि विशेष शिकायतों के बारे में विशेष कार्यवाही की जाती है तथा दीर्घावधिक उपायों के रूप में मार्गदर्शिका के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

गुजरात में तकलों (स्पिंडलों) का वितरण

794. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय विकास निगमों के माध्यम से तकलों को वितरित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में कताई तथा सूत मिलों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) बुनकर सहकारी कताई मिलों की अंश पूंजी में भाग लेने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सरकार नई हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से ऋण सहायता देती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम् और आधुनिक बनाया जा सके। आठवीं योजना के दौरान 2 नई कताई मिलों को सहायता देने और 4 वर्तमान कताई मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। यह योजना गुजरात राज्य में भी लागू है।

New Policy to Development Wool Industry

795. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently evolved a broad policy framework to develop the wool industry; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The Industrial, Trade and Fiscal policies announced by the Government are mainly with a view to develop the Indian industries including woollen industry. So far as woollen industry is concerned, it has been exempted from compulsory